2022 0 सुप्रीम(यूके) 30

नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में
मनोज कुमार तिवारी,
जे.एस. नरेंद्र कुमार त्यागी - याचिकाकर्ता
बनाम
उत्तराखंड राज्य और अन्य - प्रतिवादी
रिट याचिका (एम/एस) संख्या 945 ऑफ 2020
निर्णय लिया गया: 05-04-2022

संदर्भित अधिनियम:
भारत का संविधान: अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 254(2)
कारखाना अधिनियम: S.2(k)
औद्योगिक विवाद अधिनियम: S.1(2), S.25(l), S.25(m) , S.25(n), S.25(n)(7), S.25(o), S.38
औद्योगिक विवाद उत्तर प्रदेश नियम: R.2, R.3, R.4, R.5
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम : S.4(k), S.6(n)
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम : S.86

संदर्भित मामले:
जबर सिंह और अन्य बनाम। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और अन्य, 2003 यूडी 365 - संदर्भित
कर्मकार बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड - संदर्भित
इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड बनाम कर्मकार। - निर्दिष्ट
राष्ट्रीय अभियांत्रिकी। इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य। - निर्दिष्ट
उत्तरांचल वन विकास निगम व अन्य बनाम. जबर सिंह और अन्य, (2007) 2 एससीसी 112 - संदर्भित
यूपी शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ओमप्रकाश उपाध्याय, (2002) 10 एससीसी 89 - संदर्भित
इंजीनियरिंग कामगार यूनियन बनाम मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, (2004) 6 एससीसी 36 - संदर्भित
यूपी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम आरके शुक्ला और अन्य, मानु/एससी/0333/1969: 1969 (2) एससीसी 400 - संदर्भित
राधेश्याम और अन्य बनाम। छवि नाथ और अन्य, (2009) 5 एससीसी 616 - संदर्भित
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम। झारखंड राज्य और अन्य, (2014) 1 एससीसी 536 - संदर्भित

अधिवक्ताओं ने पेश किया:
याचिकाकर्ता के लिए: श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वीके कपरुवान द्वारा सहायता प्राप्त।
प्रतिवादी के लिए: श्री योगेश तिवारी, स्थायी वकील, श्री एम सी पंत।

निर्णय :

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत नियोक्ता की याचिका है, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, हल्द्वानी द्वारा 2019 के एडजुडिकेशन केस नंबर 04 में दिए गए अवार्ड दिनांक 02.03.2020 को चुनौती दी गई है। उक्त अवार्ड द्वारा, मेसर्स भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा 303 कामगारों की छंटनी को अन्यायपूर्ण और औद्योगिक विवाद अधिनियम (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 25-एन का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था।

2. यह विवादित नहीं है कि संदर्भ श्रम आयुक्त, उत्तराखंड द्वारा यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4-के के तहत किया गया था। विवाद का अंग्रेजी अनुवाद, जिसे निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था, नीचे दिया गया है:-

> "1 मैसर्स भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 18, सेक्टर-02, पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा 303 कामगारों की छंटनी (संलग्न सूची के अनुसार) उचित है या कानूनी, जैसा कि कामगारों का आरोप है कि छंटनी/लॉकडाउन बिना पूर्व सूचना? यदि नहीं, तो कामगार किस राहत के हकदार हैं और किस विवरण के साथ"

3. याचिकाकर्ता ने इस आधार पर निर्णय को चुनौती दी है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 25-एन को औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा छंटनी की वैधता तय करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था, जब धारा 4-के के तहत संदर्भ दिया गया था। यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। इस प्रकार, उनके अनुसार, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने संदर्भ के दायरे से परे यात्रा की है, एक निष्कर्ष दर्ज करके कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 25-एन का उल्लंघन है। इस प्रकार, प्रश्न, जो वर्तमान मामले में विचार के लिए आता है, क्या तथ्यों और परिस्थितियों में, सीखा औद्योगिक न्यायाधिकरण केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन में निहित प्रावधान को लागू करने के लिए न्यायोचित था, जब विवाद के तहत संदर्भित किया गया था। राज्य अधिनियम।

प्रतिवादी के लिए: श्री योगेश तिवारी, स्थायी वकील, श्री एम सी पंत।

निर्णय :

4. विवादित अधिनिर्णय में, कामगारों के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा उनके लिखित बयानों में किए गए कथनों को व्यापक रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया है। नियोक्ता ने स्वीकार किया कि दिसंबर, 2018 में लगभग 384 व्यक्ति कारखाने में कार्यरत थे, इसलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केंद्रीय अधिनियम) के अध्याय VB की प्रयोज्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि तकनीकी प्रगति के कारण याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में महत्वपूर्ण कमी के कारण, यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6-एन में निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए 303 कामगारों की छंटनी की गई थी, जिसे यूपी के साथ पढ़ा जाए। औद्योगिक विवाद नियम, 1957; दिनांक 27.12.2018 को नोटिस बोर्ड पर छंटनी नोटिस चस्पा कर दिया गया। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार, एक महीने के नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि सहित सभी

कानूनी बकाया, संबंधित कामगारों को चेक के माध्यम से पेश किए गए थे और 303 कामगारों में से 144 ने छटनी मुआवजा स्वीकार कर छंटनी स्वीकार कर ली थी। .

6. पैराग्राफ नं विवादित अधिनिर्णय के 9 से पता चलता है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया था कि अधिनिर्णय के लिए संदर्भित विवाद को केवल कानूनी मुद्दों पर तय किया जा सकता है और इस मामले में शामिल कानूनी प्रश्न को संबोधित करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी। विद्वान ट्रिब्यूनल ने अंतिम सुनवाई के चरण में, यदि आवश्यक हो, तो सबूत पेश करने के लिए पक्षकारों को स्वतंत्रता दी थी।

7. विद्वान औद्योगिक अधिकरण ने अधिनिर्णय में देखा कि किसी भी पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर के लिए अनुरोध नहीं किया और उन्होंने अपने तर्कों को केवल कानूनी प्रश्नों तक ही सीमित रखा, इसलिए, कानून के प्रश्न पर प्रतिद्वंद्वी तर्कों के आधार पर विवाद का निर्णय लिया गया।

8. औद्योगिक ट्रिब्यूनल के समक्ष, कामगारों ने तर्क दिया कि राज्य अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके उनकी छंटनी की गई है; जबकि, उत्तरांचल वन विकास निगम एवं अन्य बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार। जबर सिंह और अन्य, (2007) 2 एससीसी 112 में प्रतिवेदित, केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन में निर्धारित प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कामगारों ने तर्क दिया कि चूंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन में निहित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए, उनकी छंटनी गलत है और वे सभी लाभों के साथ बहाली के हकदार हैं।

9. नियोक्ता ने अपने लिखित बयान में कामगारों द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया था कि उनकी छंटनी के बाद, ठेकेदार के माध्यम से नए हाथों को यह तर्क देने के लिए लगाया गया था कि कारखाने में कोई तालाबंदी नहीं हुई है, इसलिए तालाबंदी की वैधता कोई मुद्दा नहीं है। तय।

10. ट्रिब्यूनल के समक्ष, नियोक्ता ने यूपी शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ओमप्रकाश उपाध्याय के मामले में (2002) 10 एससीसी 89 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया, यह तर्क देने के लिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में निहित प्रावधान , 1947 (केंद्रीय अधिनियम), उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है, जो यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा कवर किए गए हैं। इंजीनियरिंग कामगार यूनियन बनाम मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के मामले में दिया गया एक अन्य निर्णय, (2004) में रिपोर्ट किया गया) 6 एससीसी 36 , नियोक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में भरोसा किया गया था कि राज्य अधिनियम केंद्रीय अधिनियम के साथ प्रतिकूलता के मामले में प्रबल होगा, यदि इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया था और अनुच्छेद 254 (2) के तहत उनकी सहमति प्राप्त हुई थी। भारतीय संविधान।ट्रिब्यूनल के समक्ष, नियोक्ता ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया था। झारखंड राज्य और अन्य, में सूचना दी(2014) 1 एससीसी 536 , इस

प्रस्ताव के लिए कि ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र संदर्भ की शर्तों तक ही सीमित है, इसलिए, यह संदर्भ से परे नहीं जा सकता है।

11. ट्रिब्यूनल के समक्ष नियोक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि उत्तरांचल वन विकास निगम और अन्य बनाम के मामले में दिया गया निर्णय। जबर सिंह और अन्य (उपरोक्त) नियोक्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दी गई गलत रियायत पर आधारित है, इसलिए उक्त निर्णय को बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

12. विद्वान न्यायाधिकरण ने उत्तरांचल वन विकास निगम एवं अन्य बनाम के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए पार्टियों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को विस्तार से निपटाया है। जबर सिंह और अन्य (सुप्रा), यह निष्कर्ष निकला है कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन मामले के तथ्यों पर लागू होगी; चूंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए छंटनी गलत है।

13. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 1(2) प्रदान करती है कि यह पूरे भारत में लागू होगी। अभिव्यक्ति "समुचित सरकार" को उक्त अधिनियम की धारा 2(ए) में परिभाषित किया गया है और धारा 2(ए)(ii) के तहत, राज्य सरकार उद्योगों की कुछ श्रेणी के संबंध में उपयुक्त सरकार है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 38 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य ने औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियम, 1976 के रूप में ज्ञात नियम बनाए, जिन्हें 06.03.1976 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त नियमों के नियम 2, 3, 4 और 5 तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> “2। परिभाषा- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
>
> (ए) 'अधिनियम' का अर्थ है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;
>
> (बी) 'फॉर्म' का मतलब इन नियमों से जुड़ा एक फॉर्म है;
>
> (ग) 'धारा' का अर्थ अधिनियम की धारा है;
>
> (डी) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट अर्थ होंगे।
>
> 3. धारा 25एम के तहत कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन- (1) धारा 25एम की उप-धारा (1) के तहत किसी भी कामगार की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन या उप-धारा के तहत ले-ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन (1) उक्त खंड के 2) फॉर्म 'ए' में बनाया जाएगा और उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा पावती देय होगा और जहां आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, जिस तारीख को उक्त प्राधिकारी को दिया गया था, उक्त धारा

की उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए वह तिथि मानी जाएगी जिस पर आवेदन किया गया था।

(2) अनुज्ञा के लिए आवेदन तीन प्रतियों में किया जायेगा तथा आवेदन के साथ संबंधित कर्मकारों पर सेवा हेतु आवेदन की पर्याप्त संख्या में प्रतियाँ भी प्रस्तुत की जायेंगी।

(3) संबंधित नियोक्ता उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके लिए अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, ऐसी और जानकारी जो प्राधिकरण आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझता है, जब भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा मांगा जाता है ताकि सक्षम किया जा सके धारा 25M की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार।

(4) जहां उक्त प्राधिकारी द्वारा ले-ऑफ करने की अनुमति दी गई है, संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त को प्रपत्रों में इस तरह के ले-ऑफ के प्रारंभ और समाप्ति की सूचना देगा। क्रमशः 'बी' और 'सी' और जहां उक्त प्राधिकारी द्वारा ले-ऑफ जारी रखने की अनुमति दी गई है, नियोक्ता संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त को इस तरह के ले-ऑफ के शुरू होने की सूचना देगा। -ऑफ फॉर्म 'बी' में, अगर ऐसा नोटिस पहले ही नहीं दिया गया है, और फॉर्म 'सी' में इस तरह के ले-ऑफ को समाप्त करने की सूचना।

(5) उप-नियम (4) में संदर्भित ले-ऑफ के प्रारंभ और समाप्ति की सूचना, इस तरह के प्रारंभ या समाप्ति के सात दिनों के भीतर दी जाएगी, जैसा भी मामला हो।

4. छंटनी की सूचना और अनुमति के लिए आवेदन.- (1) धारा 25 एन की उप-धारा (1) के तहत (सी) के तहत छंटनी के लिए नोटिस फॉर्म 'डी' में ऐसे प्राधिकरण पर तामील किया जाएगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा पावती देय है और जहां नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा तामील किया जाता है, जिस तारीख को ऐसे प्राधिकरण को दिया गया था, उसे उप के प्रयोजनों के लिए नोटिस की तामील की तारीख माना जाएगा। -उक्त धारा का खंड (3)।

(2) धारा 25एन की उप-धारा (4) के तहत छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन फॉर्म 'ई' में किया जाएगा (धारा 25एफ के खंड (ए) के तहत नियोक्ता द्वारा दिए गए नोटिस की प्रमाणित प्रति के साथ और ऐसे प्राधिकरण को दिया जाएगा) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा देय पावती द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और जहां आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, जिस तारीख को राज्य सरकार या प्राधिकरण को दिया गया था, उसे वह तारीख माना जाएगा जिस पर आवेदन किया गया था उक्त धारा की उप-धारा (5) के प्रयोजनों के लिए बनाया गया था।

(3) नोटिस या, जैसा भी मामला हो, आवेदन तीन प्रतियों में तामील किया जाएगा और संबंधित कामगारों पर तामील के लिए आवेदन की पर्याप्त संख्या में प्रतियां नोटिस के साथ जमा की जाएंगी या, जैसा भी मामला हो, आवेदन .

(4) संबंधित नियोक्ता उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत राज्य सरकार या उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसे छंटनी के लिए नोटिस दिया गया है या छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, या, मामला हो सकता है, उक्त धारा 25N की उप-धारा (4), ऐसी और जानकारी जो राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण नोटिस पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझता है या, जैसा भी मामला हो , आवेदन, जब भी ऐसे प्राधिकरण द्वारा मांगा जाता है, ताकि राज्य सरकार या प्राधिकरण को इसकी अनुमति या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमति देने से इनकार करने में सक्षम बनाया जा सके, या, जैसा भी मामला हो उक्त धारा 25N की उप-धारा (5)।

5. बंद करने की अनुमति के लिए नोटिस और आवेदन.- (1) धारा 25ओ की उप-धारा (1) के तहत बंद करने का नोटिस फॉर्म 'एफ' में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा। पोस्ट पावती देय।

(2) धारा 25ओ की उप-धारा (3) के तहत एक उपक्रम को बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन फॉर्म 'जी' में किया जाएगा [धारा 25 एफएफए की उपधारा (1) के तहत नियोक्ता द्वारा दिए गए नोटिस की प्रमाणित प्रति के साथ फॉर्म 'एच'] में और राज्य सरकार को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक पावती के माध्यम से वितरित किया जाएगा और जहां आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, जिस तारीख को राज्य सरकार को वितरित किया गया था, वह तारीख माना जाएगा जिस पर उक्त धारा 25ओ की उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए आवेदन किया गया था।

(3) नोटिस, या, जैसा भी मामला हो, आवेदन तीन प्रतियों में किया जाएगा।

(4) संबंधित नियोक्ता उस राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसे बंद करने का इरादा नोटिस दिया गया है या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन दिया गया है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो राज्य सरकार आवश्यक समझे, निर्णय पर पहुंचने के लिए नोटिस, या, जैसा भी मामला हो, आवेदन, और ऐसे नियोक्ता से मांग करता है।

14. उपर्युक्त नियमों के नियम 3, 4 और 5 के अवलोकन से पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 25एम, 25एन और 25ओ में निहित प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किए गए थे। इसलिए, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या छटनी से पहले नियम 3 और 4 के तहत सक्षम प्राधिकारी को उक्त नियमों में निर्धारित प्रपत्र में नोटिस देना आवश्यक होगा । उक्त नियमों में निर्धारित प्रपत्र में नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा।

15. 1976 के पूर्वोक्त नियमों से, यह स्पष्ट है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केंद्रीय अधिनियम) में निहित प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे उद्योगों के संबंध में भी लागू किए गए थे, जिन पर राज्य अधिनियम अन्यथा लागू था। 1976 में, जब पूर्वोक्त नियम बनाए गए थे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, इसलिए, राज्य पुनर्गठन पर, उपरोक्त नियम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के आधार पर उत्तराखंड राज्य में लागू होते हैं। उत्तरांचल वन विकास निगम और अन्य बनाम का मामला। जबर सिंह और अन्य (सुप्रा), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए 1976 के पूर्वोक्त नियमों पर विचार

किया है और माना है कि ये नियम उत्तरांचल राज्य (अब उत्तराखंड) पर भी लागू हैं।पैराग्राफ नं। उक्त निर्णय के 31 से 35 नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"31 श्री भरत संगल ने, इसलिए, प्रस्तुत किया कि पेड़ों को काटने और उन्हें लॉग में परिवर्तित करने का कार्य फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 (के) के उद्देश्य के लिए निर्माण प्रक्रिया का गठन करता है और जंगल के विभिन्न क्षेत्र जहां उक्त कार्य किया जा रहा है उक्त अधिनियम की धारा 2 (एम) के प्रयोजनों के लिए कारखाने का हिस्सा बनें। इस प्रकार, अपीलकर्ता निगम की स्थापना, हमारी राय में, धारा 25-एल में निहित औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा के अंतर्गत आती है और इसलिए, अपीलकर्ता निगम की स्थापना के लिए धारा 25-एन लागू होगी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि उत्तरांचल वन निगम यूपी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तथापि, 1976 के नियमों के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एन उत्तरांचल राज्य पर लागू है और इसलिए, स्थापना के लिए अपीलकर्ता निगम की।

32. अपीलकर्ता निगम, दिनांक 31-5-1995 के साथ-साथ 31-3-1995 से 31-5-1995 के बीच जारी किए गए अन्य नोटिस जारी करते समय धारा 25-एन की दो आवश्यकताओं में से किसी का भी पालन नहीं किया अर्थात्, कामगारों को लिखित रूप में 3 महीने का नोटिस देना या उसके बदले में उन्हें 3 महीने का वेतन देना और उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति लेना, निगम द्वारा प्रतिवादी कामगारों की छँटनी खंड के प्रावधानों के विपरीत की गई थी (1) धारा 25-एन और अवैध है।

33. धारा 25-एन का खंड (7) वैधानिक रूप से प्रदान करता है कि:

"25-एन। (7) जहां उप-धारा (1) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या जहां किसी छंटनी की अनुमति से इनकार कर दिया गया है, ऐसी छंटनी को उस तारीख से अवैध माना जाएगा, जिस दिन छंटनी का नोटिस दिया गया था। कामगार और कामगार उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे जैसे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया हो।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में किया गया निवेदन स्वीकृति के योग्य है। इस प्रकार, उक्त नोटिस की तारीख से ऊपर उल्लिखित छंटनी नोटिस अवैध हैं और कामगार सभी लाभों के हकदार हैं, वर्तमान मामले में, संबंधित सभी कामगार पूरे पिछले वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल होने के हकदार हैं।

34. श्री ध्रुव मेहता ने यह भी प्रस्तुत किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एन के वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए निगम द्वारा पारित छंटनी के आदेश कानून में अवैध हैं। धारा 25-एन जो अध्याय वीबी में आती है 1976 के अधिनियम 32 द्वारा 5-3-1976 से डाला गया और जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, कुछ प्रतिष्ठानों में छंटनी, छंटनी और बंद करने से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। जिन उद्देश्यों और कारणों और परिस्थितियों के कारण इस अध्याय को अधिनियमित किया गया, जिसमें धारा 25-एन शामिल है, इस न्यायालय द्वारा वर्कमेन बनाम मीनाक्षी मिल्स

लिमिटेड में दिए गए संविधान पीठ के फैसले में चर्चा की गई है। पैरा 22 का प्रासंगिक भाग निर्धारित किया गया है । यहाँ नीचे: (एससीसी पृष्ठ 360)

"300 से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रस्तावित छंटनी के कारणों की पूर्व जांच की आवश्यकता से, धारा 25-एन छंटनी के परिणामस्वरूप प्रभावित कामगारों को होने वाली कठिनाई को रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि, शुरुआत में अपने रोजगार के लिए, एक कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से अपेक्षा करता है और लंबी अवधि में फैली सेवा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है और छंटनी उसकी आशाओं और अपेक्षाओं को नष्ट कर देती है। छटनी किये गये मजदूर को अचानक और बिना गलती के सड़क पर फेंक दिया जाता है और बेरोजगारी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। (देखें इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमेन, एससीआर पेज 36-37 पर।) अक्सर कामगार की छटनी तब होती है जब वह उम्र में बड़ा हो जाता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और रोजगार हासिल करने में युवा लोगों के साथ रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। धारा 25-एफ के तहत देय छंटनी मुआवजे से कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन यह उसे कठिनाई से निपटने में मदद करने के लिए दूर तक नहीं जा सकता है, खासकर जब औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबी हो जाती है। देश में बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार की मौजूदा स्थितियों के आलोक में छंटनी किए गए कामगार की दुर्दशा पर विचार किया जाना चाहिए।

35. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 25-एन को एक पूर्व शर्त के रूप में सरकार द्वारा पूर्व जांच करके कर्मचारियों को छंटनी से सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया था।

16. उत्तरांचल वन विकास निगम एवं अन्य बनाम के मामले में उपरोक्त आधिकारिक न्यायिक घोषणा के मद्देनजर। जबर सिंह और अन्य (सुप्रा), याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन उस मामले पर लागू नहीं की जा सकती है जहां उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत संदर्भ दिया गया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि राज्य सरकार ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए, केंद्रीय अधिनियम की धारा 25एम, 25एन और 25ओ को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया है, इसलिए, यूपी चीनी निगम लिमिटेड के मामले में निर्णय दिया गया है। वी. ओमप्रकाश उपाध्याय, रिपोर्टेड (सुप्रा) और इंजीनियरिंग कामगार यूनियन बनाम मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड (सुप्रा) तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं। वर्तमान मामले में राज्य कानून और केंद्रीय कानून के बीच कोई विरोध नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्वयं केंद्रीय अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अपनाया है और उन्हें नियम बनाकर राज्य में लागू किया है। है।उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति लेना, निगम द्वारा प्रतिवादी कामगारों की छँटनी खंड के प्रावधानों के विपरीत की गई थी (1) धारा 25-एन और अवैध है।

17. श्री राकेश थपलियाल, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि कुल 303 में से 144 कामगार, जिनकी छटनी की गई थी, ने छटनी का मुआवजा स्वीकार कर

लिया है, इसलिए, विद्वान श्रम न्यायालय ने उन 144 कामगारों के पक्ष में संदर्भ का जवाब देने में गलती की है। . इस प्रकार, उनके अनुसार, छंटनी स्वीकार करने के बाद, ऐसे कामगार किसी भी राहत के हकदार नहीं थे। उक्त निवेदन हालांकि प्रथम दृष्टया आकर्षक लगता है, तथापि, गहन छानबीन करने पर, इसमें अधिक सार नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम (केंद्रीय) की धारा 25 एन (7) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

> "25एन कामगारों की छटनी से पहले की शर्तें.—
>
> (7) जहां उप-धारा (1) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या जहां किसी छंटनी की अनुमति से इनकार कर दिया गया है, ऐसी छंटनी को उस तारीख से अवैध माना जाएगा, जिस दिन छंटनी का नोटिस दिया गया था। कामगार और कामगार उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे जैसे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया हो।

18. माना जाता है कि छंटनी का आदेश देने से पहले नियोक्ता द्वारा उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति नहीं मांगी गई थी, इसलिए, सभी 303 कामगारों की छंटनी उस तारीख से अवैध मानी जाएगी, जिस दिन कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस दिया गया था। दूसरे शब्दों में, उचित सरकार की अनुमति के बिना छंटनी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केंद्रीय) की धारा 25 एन के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करने के लिए शून्य हो जाएगी, इसलिए, भले ही कुछ कर्मचारी छंटनी मुआवजा स्वीकार करते हैं छंटनी के बाद, यह छंटनी को वैधता नहीं देगा, जो अन्यथा अवैध है।

19. कामगारों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि भले ही नियोक्ता ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6 एन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कामगार की छंटनी की थी, फिर भी धारा में निहित अनिवार्य प्रावधान के गैर-अनुपालन के लिए छंटनी खराब होगी। औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियम, 1976 द्वारा केंद्रीय अधिनियम के 25-एन, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया है। इस विवाद के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। जबर सिंह और अन्य बनाम के मामले में। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और अन्य ने 2003 यूडी 365 में रिपोर्ट दी, जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम और अन्य बनाम के मामले में पुष्टि की गई थी। जबर सिंह व अन्य (उपरोक्त)।पैराग्राफ नं। समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के 46 से 50 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

> "46 इस प्रकार, यह देखा गया है कि धारा 25K और धारा 25L की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस प्रकार अध्याय VB में निहित धारा 25N के प्रावधान आकर्षित होते हैं। श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एल के अर्थ में वन निगम एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है, सही नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।
>
> 47. श्रम न्यायालय ने माना कि चूंकि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 4-के के तहत संदर्भ दिया गया था, केंद्रीय अधिनियम की धारा 25-एन आकर्षित नहीं हुई थी। इसने यूपी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम आरके शुक्ला और अन्य मामले

में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से लागू किया है। MANU/SC/0333/1969: 1969 (2) SCC 400 में रिपोर्ट किया गया है, जैसा कि उक्त निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम में लाए गए संशोधन से पहले अध्याय V को जोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, जो निम्नलिखित पैराग्राफ से स्पष्ट है:

हमारे सामने कुछ तर्क दिया गया था कि छंटनी मुआवजे के पुरस्कार से संबंधित मामलों को निर्धारित करने में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान लागू होते हैं, न कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के। प्रश्न अकादमिक है, क्योंकि पार्टियों के बीच विवाद के बिंदुओं पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के वैधानिक प्रावधान काफी हद तक समान हैं।

48. वर्तमान मामले में अध्याय VB में निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जो यूपी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम आरके शुक्ला और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न नहीं था। (सुप्रा)। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 38) द्वारा अध्याय VB डाला गया था।

49. निर्णय संशोधन से पहले का है, पूर्वोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आकर्षित नहीं होता है।

50. अधिनिर्णयन के लिए संदर्भित छंटनी आदेश की वैधता, वैधता या अवैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि संदर्भ किस प्रावधान के तहत किया गया है, यानी या तो यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 4-के के तहत या धारा 10 के तहत केंद्रीय अधिनियम। छंटनी की वैधता का निर्णय किया जाना है कि क्या छंटनी यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम के 6-एन के प्रावधानों के अनुसार है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के समतुल्य है या धारा 25 के अनुसार है -औद्योगिक विवाद अधिनियम का एन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से आकर्षित होता है। जैसा कि इस फैसले में कहा गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, औद्योगिक विवाद अधिनियम के 25-एन को आकर्षित किया गया था, इसलिए, छंटनी आदेश की वैधता को केवल इस सवाल का निर्धारण करके तय किया जाना है कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एन के प्रावधानों का अनुपालन किया गया या नहीं।"

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि राज्य अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विवाद में छंटनी की वैधता के प्रश्न का निर्णय लेने के लिए केंद्रीय अधिनियम की धारा 25 एन को लागू करके औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया, बलहीन है। हालांकि, औद्योगिक न्यायाधिकरण या सीखा श्रम न्यायालय सीमित अधिकार क्षेत्र का एक न्यायालय है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए संदर्भ के चार कोनों के भीतर विवाद का फैसला करना है, हालांकि, यह निश्चित रूप से आकस्मिक मुद्दों पर जाने का अधिकार है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। झारखंड राज्य और अन्य, में सूचना दी(2014) 1 एससीसी 536 ने संदर्भ आदेश की तुलना में औद्योगिक

ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किया है। पैराग्राफ नं। निर्णय का 16, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "16। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय उस क़ानून का एक प्राणी है। इसे किए गए संदर्भ के आधार पर यह क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल को खुद को संदर्भ की विषय वस्तु के दायरे में सीमित रखना होगा और उससे आगे नहीं जाना होगा। यह इस न्यायालय द्वारा नेशनल इंजीनियरिंग सहित कई मामलों में लिया गया विचार है। इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य। इस कारण से उपयुक्त सरकार का यह बाध्य कर्तव्य हो जाता है कि वह संदर्भ को उपयुक्त रूप से बनाए जो पार्टियों के बीच "विवाद" की वास्तविक/सटीक प्रकृति को दर्शाता है।"

21. हालांकि, वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान ट्रिब्यूनल ने संदर्भ के दायरे से परे यात्रा की। विद्वान ट्रिब्यूनल ने लागू कानून के आधार पर 303 कामगारों की छंटनी की वैधता के सवाल पर विचार किया है। चूंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 25 एन औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियम, 1976 के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य (और उत्तराखंड भी) में लागू है, इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क है कि सवाल में छंटनी की वैधता अकेले राज्य अधिनियम की धारा 6 एन की कसौटी पर आंका जा सकता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह किसी का मामला नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने एक प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज किया है, जिसे निर्णय के लिए नहीं भेजा गया था। संदर्भ का उत्तर देते समय, एक श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को सभी लागू क़ानूनों और औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियम, 1976 पर विचार करना आवश्यक है, एक ऐसा क़ानून है, जिसे एम द्वारा आदेशित छंटनी की वैधता को देखते हुए ध्यान में रखा जाना था। /s भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड (नियोक्ता)।

22. यह न्यायालय आक्षेपित अधिनिर्णय में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाता है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

23. राधेश्याम और अन्य बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। छबी नाथ और अन्य, (2009) 5 एससीसी 616 में रिपोर्ट की गई, ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति का न्यायाधिकरणों और न्यायालयों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के लिए बहुत संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और यह आगे किया गया है यह माना कि तथ्य और कानून की गलती को सुधारने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले को देखते हुए भी आक्षेपित अधिनिर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

24. तदनुसार, रिट याचिका विफल होती है और खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।